



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21012020-215624
CG-DL-E-21012020-215624

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 21]
No. 21]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 21, 2020/माघ 1, 1941
NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 21, 2020/MAGHA 1, 1941

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)
(स्टार्ट-अप इंडिया अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 2020

फा. सं. 5(24)/2019-स्टार्टअप इंडिया.—सतत आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने तथा बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए देश में नवप्रयोग और स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा देने हेतु सशक्त परिवेश का निर्माण करने के लिए आवश्यक उपायों के संबंध में सरकार को परामर्श देने के लिए केंद्र सरकार एतद्द्वारा 'राष्ट्रीय स्टार्ट-अप परामर्श परिषद्' का गठन करती है। यह परिषद्, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित उपायों के संबंध में सुझाव देगी:

- (i) नागरिकों, विशेष रूप से विद्यार्थियों, में नवप्रयोग की संस्कृति को बढ़ावा देना;
- (ii) संपूर्ण देश, अर्द्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों सहित, में अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में नवप्रयोग को बढ़ावा देना;
- (iii) रचनात्मकता और नवप्रयोग को इन्क्यूबेशन और अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से प्रोत्साहित करना ताकि उत्पादकता और दक्षता में सुधार के लिए उन्हें मूल्यवान उत्पादों, प्रक्रियाओं या समाधान में परिवर्तित किया जा सके;
- (iv) उद्योगों में नवप्रयोग को समावेश करने के लिए वातावरण का निर्माण;

- (v) सार्वजनिक उद्यमों को नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए नवप्रयोगों को अपनाने में सहायता करना;
 - (vi) बौद्धिक संपदा अधिकारों के सृजन, संरक्षण और वाणिज्यीकरण को बढ़ावा देना;
 - (vii) विनियामक अनुपालनों और लागतों में कमी करके व्यवसाय शुरू करने, संचालन करने, आगे बढ़ाने और निर्गम करने को आसान बनाना;
 - (viii) स्टार्ट-अप्स के लिए पूंजी तक पहुंच आसान बनाने को बढ़ावा देना;
 - (ix) स्टार्ट-अप्स में निवेश के लिए घरेलू पूंजी को प्रोत्साहित करना;
 - (x) भारतीय स्टार्ट-अप्स में निवेश के लिए वैश्विक पूंजी जुटाना;
 - (xi) मूल प्रयोजकों का स्टार्ट-अप्स पर नियंत्रण बनाए रखना;
 - (xii) भारतीय स्टार्ट-अप्स को वैश्विक बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराना।
2. राष्ट्रीय स्टार्ट-अप्स परामर्श परिषद् की अध्यक्षता वाणिज्य और उद्योग मंत्री, भारत सरकार द्वारा की जाएगी।
3. इस परिषद् में निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित होंगे:

क्र.सं.	सदस्य	स्थिति	टिप्पणी
1	सफल स्टार्ट-अप्स के संस्थापक - 10 सदस्य तक	सदस्य (आधिकारिक-गैर)	केंद्र सरकार द्वारा नामित
2	ऐसे व्यक्ति जिन्होंने भारत में कंपनियों की स्थापना और विशेष विकास किया है। - 6 सदस्यों तक	सदस्य (आधिकारिक-गैर)	केंद्र सरकार द्वारा नामित
3.	स्टार्टअप्स में निवेशकों के हितों का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम व्यक्ति - 10 सदस्यों तक	सदस्य (आधिकारिक-गैर)	केंद्र सरकार द्वारा नामित
4.	इनक्यूबेटर्स और एक्सेलरेटर्स का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम व्यक्ति - 6 सदस्यों तक	सदस्य (आधिकारिक-गैर)	केंद्र सरकार द्वारा नामित
5.	स्टार्टअप्स के हितसाधक संघों के प्रतिनिधि - 6 सदस्यों तक	सदस्य (आधिकारिक-गैर)	केंद्र सरकार द्वारा नामित
6.	उद्योग संघों, जैसे सीआईआई, फिक्की, एसोचैम, नैस्कॉम के प्रतिनिधि - 6 सदस्यों तक	सदस्य (आधिकारिक-गैर)	केंद्र सरकार द्वारा नामित

4. निम्नलिखित मंत्रालयों/संगठनों के/विभागों/ नामित सदस्य, जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव के पद के स्तर से नीचे न हों, परिषद् के पदेन सदस्य होंगे:

क्र. सं.	सदस्य
1.	सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार
2.	नीति आयोग

3.	राजस्व विभाग
4.	वित्तीय सेवाएं विभाग
5.	व्यय विभाग
6.	वाणिज्य विभाग
7.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
8.	जैव प्रौद्योगिकी-विभाग
9.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग
10.	श्रम और रोजगार मंत्रालय
11.	उच्च शिक्षा विभाग
12.	स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
13.	कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय
14.	इलेक्ट्रॉनिक और सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
15.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमी मंत्रालय
16.	केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
17.	केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा बोर्डशुल्क-
18.	भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक

5. संयुक्त सचिव, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग परिषद के (स्टार्टअप्स) संयोजक होंगे। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग का स्टार्टअप इंडिया प्रभाग परिषद को सचिवीय सहायता प्रदान करेगा।
6. परिषद प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार बैठक करेगी। बैठक का कोरम बोर्ड के कुल सदस्यों का एक तिहाई होगा।
7. आधिकारिक सदस्यों के अलावा परिषद के सदस्यों के लिए यात्रामहंगाई भत्ते वित्त/ मंत्रालय, व्यय विभाग के आदेशों/दिशानिर्देशों के अनुसार विनियमित किए/ जाएंगे।
8. स्टार्टअप सलाहकार परिषद के गैर आधिकारिक सदस्यों का कार्यकाल-दो वर्ष की अवधि या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, तक रहेगा।

अनिल अग्रवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)
(STARTUP INDIA SECTION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st January, 2020

F. No. 5(24)/2019-Startup India.—The Central Government hereby constitutes the ‘National Startup Advisory Council’ to advise the Government on measures needed to build a strong ecosystem for nurturing innovation and startups in the country to drive sustainable economic growth and generate large scale employment opportunities. The council shall, *inter alia*, suggest measures to:

- (i) Foster a culture of innovation amongst citizens and students in particular;
- (ii) Promote innovation in all sectors of economy across the country, including semi-urban and rural areas;

- (iii) Support creative and innovative ideas through incubation and research and development to transform them into valuable products, processes or solutions to improve productivity and efficiency;
 - (iv) Create an environment of absorption of innovation in industry;
 - (v) Facilitate public organizations to assimilate innovation with a view to improving public service delivery;
 - (vi) Promote creation, protection and commercialization of intellectual property rights;
 - (vii) Make it easier to start, operate, grow and exit businesses by reducing regulatory compliances and costs;
 - (viii) Promote ease of access to capital for startups;
 - (ix) Incentivize domestic capital for investments into startups;
 - (x) Mobilize global capital for investments in Indian startups;
 - (xi) Keep control of startups with original promoters.
 - (xii) Provide access to global markets for Indian startups.
2. The National Startup Advisory Council shall be chaired by Minister for Commerce & Industry, Government of India.
3. The Council shall consist of the following members, namely:-

Sl. No.	Members	Status	Remarks
1	Founders of successful startups - Up to 10 members	Members (Non-official)	Nominated by Central Government
2	Veterans who have grown and scaled companies in India - Up to 6 members	Members (Non-official)	Nominated by Central Government
3.	Persons capable of representing interests of investors into startups - Up to 10 members	Members (Non-official)	Nominated by Central Government
4.	Persons capable of representing interests of incubators and accelerators - Up to 6 members	Members (Non-official)	Nominated by Central Government
5.	Representatives of associations of stakeholders of startups - Up to 6 members	Members (Non-official)	Nominated by Central Government
6.	Representatives of industry associations like CII, FICCI, ASSOCHAM, NASSCOM - Up to 6 members	Members (Non-official)	Nominated by Central Government

4. The nominees of the following Ministries/Departments/Organisations, not below the rank of Joint Secretary to the Government of India, shall be ex-officio members of the Council:

Sl. No.	Members
1.	Office of Pr. Scientific Advisor to the Government
2.	NITI Aayog
3.	Department of Revenue
4.	Department of Financial Services

5.	Department of Expenditure
6.	Department of Commerce
7.	Department of Science and Technology
8.	Department of Bio-Technology
9.	Department of Health & Family Welfare
10.	Ministry of Labour and Employment.
11.	Department of Higher Education
12.	Department of School Education & Literacy
13.	Ministry of Corporate Affairs
14.	Ministry of Electronic and Information and Technology
15.	Ministry of Micro, Small and Medium Entrepreneurs
16.	Central Board of Direct Taxes
17.	Central Board of Indirect Taxes and Customs
18.	Small Industrial Development Bank of India

5. Joint Secretary, Department for Promotion of Industry and Internal Trade (dealing with startups) shall be the Convener of the Council. Startup India Division of Department for Promotion of Industry and Internal Trade shall provide secretarial assistance to the Council.
6. The Council shall meet at least once in every quarter. Quorum of the meeting shall be one-third of the total Members of the Board.
7. Traveling/Dearness allowances to the members of the Council other than official members shall be regulated as per Ministry of Finance, Department of Expenditure's Orders/Guidelines.
8. The term of the Non-official members of the Startup Advisory Council shall be for a period of two years or until further orders, whichever is earlier.

ANIL AGRAWAL, Jt. Secy.